रिपोर्ट कार्ड

2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वतंत्र और गैर राजनीतिक ग्रुप के कुछ लोगों ने (जिन्हें लोकतंत्र और संविधान की परवाह है) देश के मतदाताओं के लिए एक अभियान चलाया है। हम चाहते हैं कि आप सही सूचना के आधार पर वोट डालें। इस क्रम में हमने सत्ताधारी दल भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादे और डिलिवरी का आंकलन किया है। इसके लिए हमने सरकारी आंकड़े प्रमाणिक रिपोर्ट्स का सहारा लिया है। इस रिपोर्ट में किए गए सभी आंकलन का हमारे पास ठोस आधार है।

कोई भी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र को गंभीरता से नहीं लेती है। सभी पार्टियों के घोषणापत्र वादों से भरे होते हैं लेकिन काम उस अनुपात में बेहद कम होते है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बेहद निराश किया है। वे जितने दावे कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर बढ़ा-चढा कर पेश किए गए हैं।

https://novoterleftbehind.in/

हमारे निष्कर्षों का सारांश

भाजपा के घोषणापत्र में किए गए वादे	डिलिवरी
भ्रष्टाचार	👎
रोजगार और उद्यमिता	👎
नोटबंदी	👎
महंगाई	👎
सरलीकृत कर व्यवस्था	👎
आधारभूत संरचना	👎
मेक इन इंडिया	👎
उद्योग	👎
कृषि	👎

भाजपा के घोषणापत्र में किए गए वादे	डिलिवरी
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग	👍
ग्रामीण भारत	👍
एससी,एसटी, ओबीसी	👎
महिलाएं	👎
अल्पसंख्यक	👎
स्वास्थ्य	👍
संस्थागत सुधार	👎
संस्कृती एवं विरासत	👍
जम्मू एंड कश्मीर	👎

📣 भाजपा घोषणापत्र में किए वादे 👍 वादों के अनुरूप काम 👍 परिवर्तन नहीं 👎 वादे पूरे नहीं हुए

भ्रष्टाचार

लोकपाल की नियुक्ती करना

कार्यकाल समाप्त होने के अंत में

लोगों को सशक्त करने के लिए
सूचना की उपल्बद्धता

आरटीआई के लिए पैंडिंग आवेदन

2014-15 **8.5 लाख**

2017-18 **14.5 लाख**

40% केस रिजेक्ट किए गए

केंद्रीय सुचना आयोग द्वारा

11 खाली पदों में से सिर्फ 3 पदों पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए

1700+ रिट पिटिशन

केंद्र सरकार द्वारा लोगों को
सूचना नहीं देने के लिए

चुनावी खर्चे में कमी लाएंगे

5 बिलियन यूएस डॉलर, अब तक के सबसे
ज्यादा 2014 में भाजपा ने खर्च किया

भाजपा को अज्ञात स्रोत्रों से मिलने वाले चंदे
में 2017-18 के दौरान 4 गुना की वृद्दी

95%

बीजेपी को इलेक्टोरल
बॉन्ड के जरिए अज्ञात
स्रोत से फंडिंग

कथित भ्रष्टाचार की घटनाएं

3.4 लाख करोड़ का

राजस्थान रिफाइनरी घोटाला

50,000 करोड का

अदानी ग्रुप का पावर घोटाला

20,000 करोड़ का

गुजरात का जीएसपीसी घोटाला

14,500 करोड़ का
हुडको स्कैम

11,300 करोड़ का

नीरव मोदी घोटाला

9,000 करोड़ का

बाल्को डिसइनवेस्टमेंट घोटाल

9,000 करोड़ का विजय माल्या घोटाला

7,000 करोड़ का

ललित मोदी घोटाला

2,000 करोड़ का

दाल घोटाला

400 करोड़ का

मत्स्य घोटाला

80 करोड़ का

जय शाह घोटाला

राफेल घोटाला

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

रोजगार और उद्यमिता

श्रम क्षेत्र को बढ़ावा देंगे

निर्यात ग्रोथ रेट	रेडिमेड गारमेंट	कपड़ा उद्योग रेडिमेड गारमेंट को छोडकर	रत्न और आभूषण	चमड़ा और चर्म उत्पाद
अप्रैल 2014	30%	30%	2%	40%
अप्रैल 2018	-20%	5%	-15%	0%

बीजेपी रोजगार सृजन को प्राथमिक्ता देगी

और उद्यम को मौका देगी

एनएसएसओ: बेरोजगारी 45 सालों में चरम पर

2017-18 **6.1%**

नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद,
भारत की श्रम भागीदारी 45% गिर गई;
कार्यशील जनसंख्या का 2 % यानी की लगभग 13
मिलियन श्रम बाजार से बाहर हो गया

नौकरी गई

दिसंबर 17 to दिसंबर 18 **11 मिलियन**

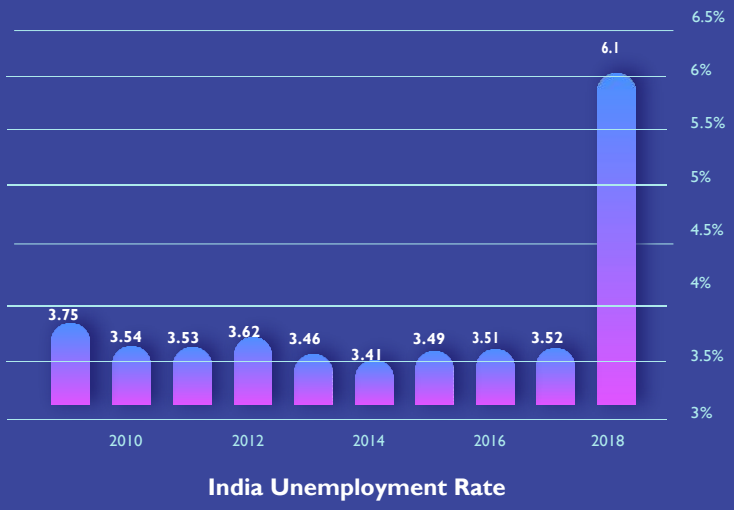

India Unemployment Rate

हम वैश्विक स्तर निवेश एवं औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए माहौल बनाएंगे

निर्माण को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेश में गिरावट आई

- निर्माण एवं रियल एस्टेट
- सेवाएं (वित्त के अलावा)
- बिजली
- खनिज
- विनिर्माण

भारत में नए निवेश (सार्वजनिक और निजी) 2018 की दिसंबर तिमाही में 14 साल के निचले स्तर तक पहुंच गए हैं।

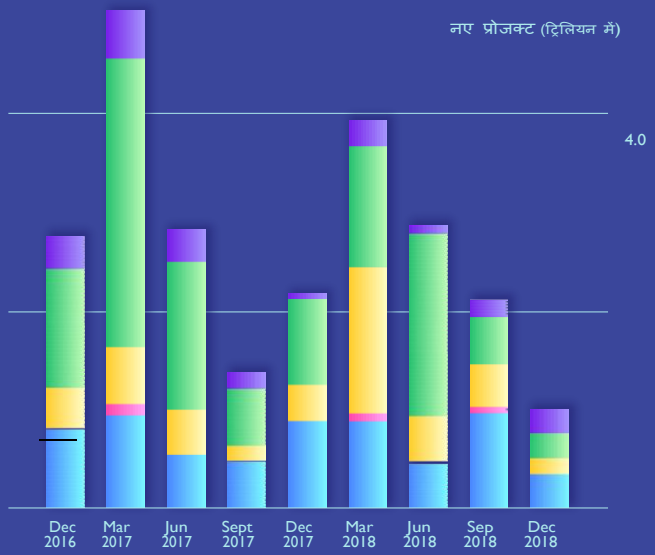

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

नोटबंदी

असंगठित क्षेत्र में जॉब्स खत्म

99% से ज्यादा नोट बैंक में वापस

35 लाख नौकरियां खत्म

1.5 करोड़ लेबर फोर्स में कमी

1.5%
जीडीपी दर में गिरावट

2.25 लाख करोड़
जीडीपी को नुकसान

13,000 करोड़
आरबीआई को नोटबंदी पर खर्च करना पड़ा

महंगाई

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे

नहीं बना

मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाएंगे

महज 500 करोड़ खर्च कर छोटा सा फंड

खाद्य मूल्य

खाद्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर

अप्रैल 2014	नवंबर 2018
9.2%	**-2.61%**
महंगा जीवन यापन	डिफ्लेशन से किसान परेशान

सरलीकृत कर व्यवस्था

लालफीताशाही को खत्म करना, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करना एवं बाधाओं को दूर करना

1 Lakh करोड़
की राजस्व संग्रह में कमी

50% से ज्यादा
2017-18 में नियमित करदाताओं के अनुपालन में कमी

करीब 900
नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव की वजह से नुकसान

एंजल टैक्स

भारत में 70 प्रतिशत से ज्यादा स्टार्टअप्स टैक्स की सम्स्या से जूझ रहे हैं

कुछ मामलों में टैक्स रिटर्न की 30 प्रतिशत तक है

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

आधारभूत संरचना

डायमंड चतुर्भुज परियोजना

1 भी कॉरिडोर पूरा मंजूर नहीं किया गया

दिल्ली,मुंबई,कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए पहचान किए प्रोजेक्ट में से

बुलेट ट्रेन

काम शुरू होना बाकी

जापान से लोन	**1 लाख करोड़**
लोन की किस्त	**अभी नहीं मिला**
भूमि अर्जन	शुरू नहीं हुआ
इससे नौकरी का वादा	मात्र **4000**

सबको कम लागत का घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर (शहरी और ग्रमीण क्षेत्र में)

एनडीए -2	**1.03 करोड घर**
यूपीए -2	**1.21 करोड घर**
भारत में बेघर लोगों की संख्या	**18 करोड़**

मेक इन इंडिया

निर्माण क्षेत्र

रोजगार को बढ़ावा देंगे

जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा

2014	**15.07**
2017	**15.0**

मासिक विनिर्माण (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)

मई 2014	**4.6**
मई 2018	**2.8**

एफडीआई में विनिर्माण

यूपीए -2	**44%**
एनडीए -2	**28%**

उद्योग

रचनात्मक व्यवसाय करने के लिए उत्साहवर्धन

इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक

2014	**142**
2018	**77**

बहुराष्ट्रीय ब्रांड का खुदरा क्षेत्र में प्रवेश नहीं

वॉल-मार्ट और कैरेफोर जैसी विदेशी खुदरा विक्रेताओं को खुदरा क्षेत्र में 100 % इजाजत

लघु एवं कुटीर उद्योग

इस क्षेत्र का श्रेय

मार्च 2015	**11.2%**
दिसंबर 2016 (नोटबंदी के बाद)	**-2%**
मई 2018 (साल दर साल दर)	**8.4%**

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

कृषि

किसानों को लागत से कम से कम 50 % ज्यादा लाभ

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गईं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रति किसान मुआवजे की वास्तविक राशी	**1000 या कम**
हर साल बीमा कंपनियों को होने वाले मुनाफे	100 करोड़ का

किसान आत्महत्या

साल 2016 से सरकार ने आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं।

आत्महत्या कम होने की संभावना नहीं - खाद्य कीमतों में गिरावट के साथ कृषि संकट बढ़ा है। समर्थन मुल्य मे मामूली बढ़त हुई है।

असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की स्थिति

असंगठित क्षेत्र में काम रहे लेबर्स को पहचान पत्र

1% से भी कम

असंगठित श्रमिकों के लिए 45 करोड़ पहचान संख्या (लिन)

श्रमिकों को समर्पित बैंक

अबतक नहीं बना

जन धन योजना

निष्क्रिय/शून्य-शेष खाते की संख्या

2014	**77%**
2019	**30%**

पेंसन और स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा

2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा

अबतक किसी को भी लाभ नहीं

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

ग्रामीण भारत

हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, किसी भी मौसम में गांव का संपर्क न टूटे

जून **2014 - 56%**

टारगेट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा किया गया

जुलाई **2018 - 88%**

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरा किया गया

हर दिन नेशनल हाईवे बने

2013-15	12 किलोमीटर प्रतिदिन
2017-18	27 किलोमीटर प्रतिदिन

औसतन हर दिन सड़क बने

2013-14	**69 किलोमीटर**
2017-18	**134** किलोमीटर

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना "हर खेत को पानी"

10%

प्रोजेक्ट वाटरशेड विकास के तहत सिर्फ पूरे।

99 में से 74 प्रेजेक्ट्स के काम पेंडिंग

निर्माण लंबित

मनरेगा

8,000 करोड़	**20,000** करोड़
जनवरी 2019 तक मजदूरी बकाया	बजट 2019-20 में आवंटन में कमी

अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के गरीबों तबकों के लिए पर्याप्त बजट

2019 के अंतरिम बजट में आवंटन

अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना

जरूरत :	16.6%
आवंटित बजट :	2.32%

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना

जरूरत:	**8.6%**
आवंटित बजट :	1.6%

समाजिक न्याय एवं समाजिक सद्भाव

संसद ने अनुसुचित जाति और जनजाति(अत्याचार) संसोधन विधेयक,2018 पास किया

- लेकिन सिर्फ 147 करोड़ रुपए दलित महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिए गए
- लगभग 750 करोड़ गौ संरक्षण के लिए दिए गए
- जब अप्रैल 2018 में दलित विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उनका क्रूर दमन किया गया

'दलित,आदिवासी और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बोलने वाले कार्यकर्ताओं पर तरह के जुल्म हुए

आरक्षण का कार्यान्वयन

90% की गिरावट

2014-15 में एससी-एसटी-ओबीसी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सीधी भर्ती में

आदिवासियों की जमीनों को अलग रखना

राज्य द्वारा वन अधिकार अधिनियम की रक्षा न होने की वजह से करीब 10 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार बेदखली का सामना कर रहे हैं।

वन बंधु कल्याण योजना(VBKY)

बजट आवंटन

2015-16	**200 करोड़**
2017-18	**1** करोड़

आदिवासी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र भी नहीं स्थापित किया गया

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

महिलाएं

संविधान संसोधन के द्वारा पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली में 33 % रिजर्वेशन

महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ

महिलाओं के खिलाफ अपराध - महिलाओं से संबंधित नियमों का मजबूत कार्यान्वयन, खासकर बलात्कार से संबंधित

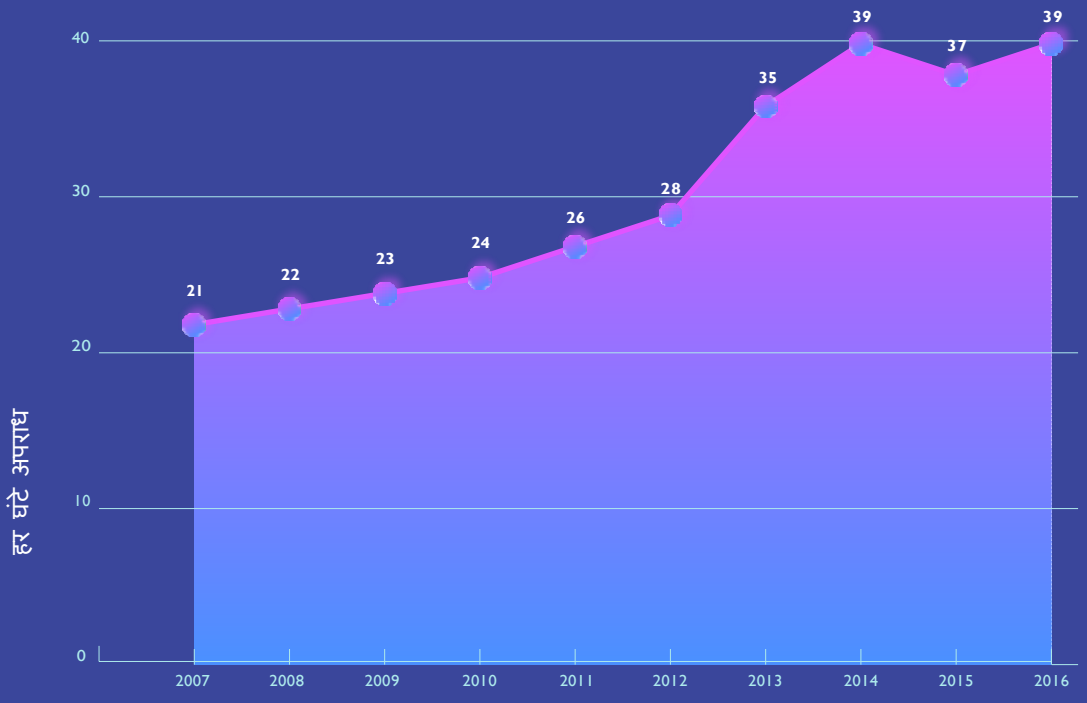

भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, 2007- 2016

2016 के बाद से रष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं

बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंक

	कुल	शिक्षात्मक प्राप्ति	स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
2014	114	126	141
2018	108	114	147

स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता संकेतकों में वैश्विक स्तर पर समग्र रैंकिंग में मामूली सुधार लेकिन वास्तविक गिरावट

अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

1984 सिक्ख विरोधी दंगों में

आरोपी सज्जन कुमार को सजा

2002 मुस्लिम विरोधी दंगो में

माया कोडनानी,बाबू बजरंगी जैसे हाई प्रोफाइल आरोपी बरी

गाय को लेकर मॉब लिंचिंग

125 घटनाएं

297 पीड़ित

46 मौतें

लगभग सभी पीड़ित मुस्लिम

तीन तलाक

मुस्लिम महिलाओं के लिए

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पास। जिसमें तलाक देने के आरोपी पति को जेल का प्रावधान

हिंदु महिलाओं के लिए

भाजपा ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश वाले समान अधिकार का विरोध किया

नागरिक संसोधन बिल

मुस्लमानों को बाहर रखा गया

शरणार्थियों को नागरिकता देने के क्रम में मुस्लमानों को बाहर रखा गया।

असम समझौता

लोगों की भावनाएं आहत हुई जिससे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में विरोध प्रदर्शन

सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देंगे और स्वास्थ्य पर हो रहे खर्चे कम करेंगे

स्वास्थ्य बजट में मामूली बढ़ावा

2014 **1.83%**

2019 **1.99%**

आयुष्मान भारत

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बजाए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है

नेशनल हेल्थ मिशन बजट

2014-15 स्वास्थ्य बजट का **61%**

2019-20 स्वास्थ्य बजट का **49%**

सरकारी खर्चे का 2.4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर – 2014 से 19 के बीच स्वास्थ्य हिस्सेदारी में स्थिरता

आईटी आधारित हेल्थ केयर डिलिवरी

नेहा(राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण) और दिक्षा (हेल्थकेयर एक्ट में डिजिटल सूचना सुरक्षा) में काम चल रहा है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में नागरिकों के हेल्थ डेटा खतरे में है।

हर राज्य में एम्स जैसे संस्थान

2014 के बाद से 22 नए एम्स की घोषणा की गई

मंगलागिरी,नागपुर,गोरखपुर,कल्याणी,असम, हिमाचल प्रदेश,पंजाब,तमिल,तमिलनाडु,बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, झारखंड और अन्य स्थानों पर।

इनमें से कोई भी प्लानिंग स्टेज से आगे नहीं बढ़ा है।

गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छ कर देना

28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया

लेकिन खुले में सौच की रिपोर्ट कई जगहों से आई

हाथ से सफाई को रोकने के लिए कोई पहल नहीं

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए

संस्थागत सुधार

अधीनस्थ न्यायालयों में जजों और कोर्ट की संख्या दोगुनी करेंगे

5,223

पद ट्रायल कोर्ट में खाली पड़े हैं।

2,76,74,499

केस अधिनस्थ न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हैं।

22,036

पद उच्च और निम्न न्यायिक अधिकारियों के खाली पड़े हैं।

न्यायपालिका के हर स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट

कार्यरत फास्ट ट्रैक

मार्च 2017 **524**

उसके बाद नहीं बढ़े

सांस्कृति एवं विरासत

अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा

नहीं बना

मवेशियों के लिए राष्ट्रीय विकास बोर्ड यूपी में गठित किया जाएगा

2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गठित

समान नागरिक संहिता

नहीं बना

लॉ कमीशन ने कहा है कि इसकी न तो जरूरत है और न ही इसे बनाने की चाह

जम्मू कश्मीर

444

लोग 2018 में आतंकी गतिविधियों में मारे गए जो 2009 के बाद सबसे ज्यादा है।

2013	6
2017	126

मारे गए आतंकवादी

2008	339
2018	250

93%

आतंकी घटनाओं में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धी। 2014 - 18 के बीच।

176%

जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धी हुई है।

28

आतंकी घटना 2014-18 के बीच हर महीनें हुए हैं।

भाजपा घोषणापत्र में किए वादे | वादों के अनुरूप काम | परिवर्तन नहीं | वादे पूरे नहीं हुए